

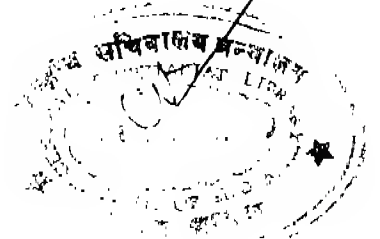


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1992/चैत्र 11, 1914

No. 148] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

(आयकर)

सा.का.नि. 381(अ).—यतः आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं ब्राजील संघात्मक गणराज्य की सरकार के बीच अनुबद्ध अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया गया है तथा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 द्वारा यथोपेक्षित अनुसमर्थन के निबन्धों का ब्राजिलिया में दिनांक 11 मार्च, 92 को आदान-प्रदान किया गया है;

तथापि, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबंधों को भारत संघ में लागू किया जाएगा।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील के संघीय गणराज्य की सरकार के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और ब्राजील के संघीय गणराज्य की सरकार ने आयकर पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमति व्यक्त की है :

अनुच्छेद 1

वैयक्तिक विषय-क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय जिन करों पर लागू होगा, वे इस प्रकार हैं :

(क) ब्राजील के मामले में :

—संघीय आयकर, अनुपूरक आयकर तथा मामूली महत्व के कार्य कलापों पर लगने वाले कर को छोड़कर (इसे एतद्वश्यात "ब्राजील कर" के रूप में कहा गया है);

(ख) भारत के मामले में :

(1) आयकर जिसमें उस पर उद्ग्रहणीय कोई भी अधिभार शामिल है;

(2) अतिकर;

(इसे एतद्वश्यात "भारतीय कर" के रूप में कहा गया है)।

2. यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप से एक समान करों पर भी लागू होगा जो ऊपर उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद लगाये जायेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय के उद्देश्य के लिए जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) सभी व्यक्ति जिन्हें किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता प्राप्त है;

(2) सभी वैध व्यक्ति, भागीदारी तथा संगठन को किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अन्तर्गत इस प्रकार की अपनी हैसियत रखते हैं;

(ख) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार ब्राजील अथवा भारत अभिप्रेत है;

(ग) "व्यक्ति" शब्द से कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में प्रवर्तमान कराधान कानूनों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

(घ) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जो करों के प्रयोजनार्थ एक निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(च) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों का अभिप्राय किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है जिसका संचालन कोई ऐसा उद्यम करता हो जिसका एक संविदाकारी राज्य में अपनी प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान हो, सिवाय इसके कि जब उक्त जलयान अथवा वायुयान अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के बीच ही चलाया जाता है;

(छ) "कर" शब्द से विषयगत पाठ के अनुसार "ब्राजील कर" अथवा "भारतीय कर" अभिप्रेत है;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है :

(1) ब्राजील के बारे में : वित्त मंत्री, संघीय राजस्व का सचिव, अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(2) भारत के बारे में : केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय को लागू किए जाने का संबंध है, किसी शब्द का, जो इसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वह अर्थ होगा जो उस राज्य में करों से संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ हो, जो इस करार पर लागू होते हैं।

अनुच्छेद 4

आर्थिक अधिवास

इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत है—कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान अथवा इससे मिलती-जुलती किसी अन्य कसौटी के कारण, उस राज्य में कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

जहाँ पैरा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैसियत निम्नानुसार निश्चित होगी :

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं। (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है) ;
- (ख) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसके पास संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका कोई व्यावहारिक आवास हो ;
- (ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है ;
- (घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण से, किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्दों से कारोबार वह एक निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ से उद्यम का उक्त कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (क) प्रबन्ध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;

- (च) कोई खान, कोई तेल अथवा गैस कूप, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा ऐसेम्बली परियोजना जो छः महीने से अधिक समय तक कायम रहे ;
- (ज) कोई प्रतिष्ठान, प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान अथवा समन्वेषण के लिए प्रयुक्त ट्रिलिंग रिंग, अथवा जलयान, लेकिन केवल तब जब छः महीने से अधिक की अवधि तक कायम रहे।

3. इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
- (ग) उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव,
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का क्रय करने अथवा उनके बारे में सूचना संग्रहीत करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी निम्न स्थान का रख-रखाव ;
- (ङ.) उद्यम के लिए प्रारंभिक अथवा सहायक किःम के किसी अन्य कार्यकलाप के संचालन के प्रयोजनार्थ अनन्य रूप से कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहाँ किसी स्वतंत्र हैसियत से किसी अभिकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति, जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो, किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तथा किसी संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के लिए संविदाएं सम्पन्न करने के लिए प्राधिकार का प्रायः प्रयोग करता हो, तो ऐसे मामले में उस उद्यम का किन्हीं ऐसे कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें वह व्यक्ति उस उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति के कार्यकलाप पैराग्राफ 3 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित हों, जब तक कि कारोबार के किसी निश्चित स्थान के माध्यम से कार्यकलाप किए गए हों, उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधधीन कारोबार का निश्चित स्थान एक स्थायी संस्थापन नहीं बनेगा।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से एक स्थायी संस्थापन का स्थित होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा एक स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु, जब इस प्रकार के किसी एजेंट के कार्य-कलाप स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से, जो उस पर नियंत्रण रखते हैं, अथवा जो उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं अथवा उस पर एक समान नियंत्रण रखते हों, पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किए जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा किसी ऐसे कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से अर्जित आय (इसमें कृषि अथवा वन सम्पत्ति से प्राप्त आय भी शामिल है) पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" शब्दों की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत की जाएगी, जिसमें संदर्भाधीन सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल सम्पत्ति के उप-साधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के सू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार तथा खनिज भंडार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन अथवा संचालन-अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों का अधिकार। जलयानों तथा वायुयानों को अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ (1) और (3) के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय के साथ-साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए हस्तेमाल में लाई गई अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर सकेगा, जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार करता हो, तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा परन्तु केवल उतने ही लाभों पर कर लगेगा जितने उक्त स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए हों।

2. पैराग्राफ (3) के उपबंधों के अध्वधीन जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसकी उन लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह समरूप अथवा उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों के अन्तर्गत समरूप अथवा एक-समान कार्यकलापों में लगा हुआ एक निर्दिष्ट तथा अलग उद्यम होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यापार करता होता।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति संबंधित संविदाकारी राज्य के कानूनों के उपबंधों के अनुरूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजन के लिए व्यय की गयी हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हों।

4. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. जहां लाभों में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका विवेचन इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा वायु-परिवहन

1. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा जिसमें उद्यम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान स्थित है।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान किसी जलयान में स्थित है तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जल-

धान का अपना बंदरगाह स्थित है, अथवा यदि उस जलयान का अपना ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है तो उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें उस जलयान का संवाहन एक निवासी है।

3. किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अधिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर पैरा (1) के प्रावधान भी लागू होंगे।

4. "जलयान अथवा वायुयान के परिचालन" शब्दों से जलयान अथवा वायुयान के स्वामियों, पट्टेदारों अथवा चार्टरों द्वारा किए जा रहे व्यक्तियों, डाक, पशुधन अथवा माल के परिवहन के कारोबार से अभिप्रेत है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री करना भी शामिल है।

अनुच्छेद 9

संबद्ध उद्यम

जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वही व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते हैं,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से विभिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसे मामले में किसी ऐसे लाभों की जो, उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जाएगा और वे तदनुसार करा-धेय होंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी को, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पनी उस राज्य के कानूनों के अनुसार वहां की निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता एक ऐसी कम्पनी है जो लाभांशों की लाभभोगी स्वामी है, तो इस प्रकार

प्रभारित कर की एक लाभांशों की कुल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इस पैराग्राफ में उस कम्पनी के काराधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके लाभों में से लाभांशों की अदायगी की जाती है।

3. इस अनुच्छेद में बताने-प्रबुद्ध "लाभांशों" शब्द का अन्विष्टान ऐसे शेयरों, "जोइसेस" शेयरों या "जोइसेस" अधिकारों से, खतम अधिकारों, संस्थापकों के अधिकारों अथवा अन्य अधिकारों से, जो श्रृंखला-युक्त नहीं हों और लाभों के सहभाग हैं, प्राप्त लाभ के साथ-साथ अन्य निम्नलिखित अधिकारों से प्राप्त आय से भी है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त लाभ पर लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का लाभभोगी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसको लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन से गायब से व्यापार करता है, और जिस सम्पत्ति के कारण लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावों रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां किसी भारतीय निवासी का ब्राजील में कोई स्थायी संस्थापन है, वहां उस स्थायी संस्थापन पर ब्राजील कानूनों के तहत खोद पर कर लगेगा। लेकिन ऐसे कर की मात्रा उस स्थायी संस्थापन के सकल लाभों को सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी बिन लाभों का निर्धारण उनसे संबंधित निम्नलिखित कर की अदायगी के पश्चात् किया गया हो।

6. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, जहां तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों अथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, जो उस राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन से गायबी रूप से सम्बद्ध है, उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर की किसम का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के ही रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज के उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य में कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का लाभभोगी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रसारित कर की राशि ब्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के अन्वयः—

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को, उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या किसी एजेंसी (किसी वित्तीय संस्था सहित) को जिनका स्वामित्व पूरी तरह से उक्त सरकार या राजनैतिक उप-प्रभाग के पास है, अदा किए जाने वाले ब्याज पर प्रथमोक्त राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, जब तक कि उन पैराग्राफ (ख) लागू नहीं हो;

(ख) एक संविदाकारी राज्य, अपने किसी राजनैतिक उप-प्रभाग या किसी एजेंसी (किसी वित्तीय संस्था सहित) जिसका अन्तर्विष्ट हो।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का लाभभोगी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

6. पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट कर की सीमित दर एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज और उस दूसरे संविदाकारी राज्य जो किसी तीसरे राज्य में स्थित हो, के किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन को अदा किए जाने वाले ब्याज पर लागू नहीं होगी।

7. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में ब्याज उद्भूत माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं यह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है जिसके संबंध में वह ऋण-उत्पन्न हुआ था जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी थी, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन स्थित है।

8. जहाँ ब्याज अदा करने वाले तथा लाभभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, उस ऋण-दावे

का ध्यान में रखा हुआ है, जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, ब्याज की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, ब्याज अदा करने वाले और लाभभोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, तो ऐसे मामले में एक अनुच्छेद के अन्वय में अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, ऐसे रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी उसी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों का लाभभोगी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर निम्न-लिखित से अधिक नहीं होगा :—

(क) ट्रेड मार्क के उपयोग से उत्पन्न होने वाली रायल्टियों अथवा ट्रेड मार्क के उपयोग के संबंध में अधिकार से उत्पन्न रायल्टियों की सकल रकम का 25 प्रतिशत;

(ख) सभी अन्य मामलों में रायल्टियों की सकल रकम का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “रायल्टियां” शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिसमें दूरदर्शन यद्यपि रेडियो से प्रसारण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चलचित्र, फिल्म अथवा टेपें शामिल हैं) के किसी कॉपीराइट, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा साउंड, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कार के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों का लाभभोगी स्वामी, जो उस संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, और जिस अधिकार या सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां अदा की जाती हैं वह उस स्थायी संस्थापन से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 में, प्ररूप 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 1

[नियम 3(ख), 5(2), 5(3) और 5(6) (ii) देखिए]

परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ग्रहण/अभिक्रियान्वयन/परिवहन/भंडारकरण/व्ययन के लिये प्राधिकार/प्राधिकार के नवीकरण के लिये आवेदन।

प्रेषक :

सेवा में,

सदस्य सचिव,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

महोदय,

मैं/हम _____ परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण/ग्रहण/अभिक्रियान्वयन/परिवहन/भंडारकरण/व्ययन के लिये परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन प्राधिकार/प्राधिकार के नवीकरण के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं।

केवल कार्यालय प्रयोग के लिये :

1. कोड सं. :
2. क्या यूनिट पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यथापरिलक्षित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है।

आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिये :

भाग क—साधारण

3. (क) स्वामी/अधिष्ठाता का नाम :

(ख) यूनिट का नाम और पता तथा क्रियाकलाप की अवस्थिति :

(ग) प्राधिकार जिसके लिये अपेक्षित है। (कृपया समुचित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों पर सही का निशान लगाएं)

- (1) संग्रहण
- (2) ग्रहण
- (3) अभिक्रियान्वयन
- (4) परिवहन
- (5) भंडारकरण
- (6) व्ययन

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीम

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को किसी ऐसी कम्पनी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, के निदेशक-समूह अथवा किसी परिषद् के एक सदस्य की हैसियत से, प्राप्त निदेशक की फीम तथा उससे मिलते-जुलती किसी की अन्य अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को मनोरंजन-कर्ता, जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों से प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी को अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी स्थिति में उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14, और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्यकलाप किये जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को एक संविदाकारी राज्य में सम्पन्न किए गए कार्यकलापों से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य के अधिन के लिए पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य, जिसमें उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, द्वारा प्रायोजित की गई अथवा उसकी सार्वजनिक निधियों में से सहायता की जाती है।

अनुच्छेद 18

पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अदायगियां

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त पेंशन और इससे मिलते-जुलते अन्य पारिश्रमिक, निर्वाह-व्यय तथा वापिक वृत्ति पर कर उस राज्य में लगेगा।

2. तथापि, ऐसी पेंशन तथा इससे मिलते-जुलते अन्य पारिश्रमिक, निर्वाह-व्यय तथा वापिकी पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, अगर इसकी अदायगी दूसरे

राज्य के निवासी या उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के द्वारा की गई है।

2. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी सार्वजनिक योजना के अधीन अदा की गई पेंशन तथा अन्य अदायगियों पर, जो कि किसी संविदाकारी राज्य अथवा उस राज्य के किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा पद्धति का एक भाग है, उसी राज्य में कर लगेगा।

4. जैसा कि इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है :—

(क) “पेंशन अथवा अन्य इस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक” शब्दों का तात्पर्य पूर्ववर्ती नियोजन के प्रतिफल में अदा की गई आवधिक अदायगियों अथवा पूर्ववर्ती नियोजन के सम्बन्ध में शारीरिक हानि के लिए अदा की गई क्षतिपूर्ति को रकम से है।

(ख) “वापिकी” शब्द का अर्थ उस निश्चित राशि से है जो राशि के रूप में अथवा राशि के मूल्य के बराबर पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के बढ़ने में अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन-पर्यन्त अथवा किसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चय समयावधि के दौरान निश्चित समय पर आवधिक रूप से देय हो।

अनुच्छेद 19

सरकारी भुगतान

1. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को, उस राज्य अथवा किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किया गया पारिश्रमिक, जिसमें पेंशन शामिल नहीं हो, केवल उसी राज्य में कराधेय होगा।

तथापि ऐसे पारिश्रमिक पर उस स्थिति में केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा जिसमें प्राप्तकर्ता एक निवासी है, लेकिन तब यदि सेवाओं उस राज्य में ही की जाती है और पारिश्रमिक का प्राप्तकर्ता उस राज्य का निवासी है, जो :—

(क) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; या

(ख) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य के लिए की गई सेवाओं के लिए अदा की गई अथवा उसके द्वारा सृजित की गई निधियों से अदा की गई पेंशन पर उस राज्य में कर लगेगा।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारखाने के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में अदा किए गए पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

अध्यापक और अनुसंधित

1. कोई भी व्यक्ति जो किसी संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो प्रथमोक्त राज्य की सरकार अथवा प्रथमोक्त राज्य के किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, संग्रहालय अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक संस्थान के आमंत्रण पर अथवा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत उक्त राज्य में अध्यापन के उद्देश्य से, व्याख्यान देने अथवा ऐसे संस्थान में अनुसंधान के कार्यक्रमों के प्रयोजनों से लगातार दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपस्थित रहा हो तो उस व्यक्ति को उक्त राज्य में उसके ऐंग् कार्यकलापों से मिलने वाले पारिश्रमिक पर कर से छूट मिलेगी, बशर्ते कि उसके द्वारा प्राप्त ऐसे पारिश्रमिकों की अदायगियां उक्त राज्य से बाहर प्राप्त की गई हों।

2. यह अनुच्छेद अनुसंधान से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो।

अनुच्छेद 21

छात्र और प्रशिक्षु

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण-शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा प्राप्त की गई अदायगियों पर उस राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत होती हों।

2. पैराग्राफ 1 में शामिल नहीं किए गए अनुदान, छात्र-वृत्ति तथा रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक के सम्बन्ध में पैराग्राफ 1 में उल्लिखित उस विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान उन करों में वैसी ही समान छूटें, राहतें अथवा कटौतियां मिलेंगी जो उस राज्य के निवासियों को उपलब्ध होंगी जिस राज्य में वह दोरे पर है।

3. इस अनुच्छेद का लाभ केवल उसी अवधि के लिए मिलेगा जो शुरू की गई शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा

करने के लिए उचित अथवा व्यवहारतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को उस राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से लगातार पांच वर्षों की अवधि से अधिक की अवधि के लिए इस अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मदें जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं और जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है उन पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

अनुच्छेद 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

1. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबन्धों के अध्वनीन जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी कोई ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर, इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है, ऐसे मामले में प्रथमोक्त राज्य उस निवासी की आय पर लगने वाले कर में से, अन्य राज्य में अदा किए गए आयकर के बराबर की रकम की कटौती की अनुमति देगा।

लेकिन ऐसी कटौती की रकम, उस कटौती के दिए जाने से पूर्व यथा संगणित करके उस भाग से अधिक होगी जिसे उस आय से प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित कटौती के लिए उस दूसरे राज्य में अदा किए गए कर को अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित ब्याज की और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2-ख में उल्लिखित राधटियों की सकल राशि के 25 प्रतिशत की दर से सदैव अदा किया गया समझा जाएगा बशर्ते इस प्रकार अदा किए गए समझे गए कर की रकम प्रथमोक्त राज्य में उस आय पर लगाये जाने योग्य कर से ज्यादा नहीं होगी।

3. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, ऐसा लाभान प्राप्त करती है जिस पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, ऐसे मामले में प्रथमोक्त राज्य इस प्रकार के लाभानों को कर से छूट देगा।

4. जहां भारत का कोई निवासी ऐसे लाभ प्राप्त करता है जिन पर अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 के उपबन्धों के अनुसार बाजील में कर लगाया जा सकता है, ऐसे मामले में भारत इस प्रकार के लाभानों को कर से छूट देगा।

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन सम्बन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक-समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के एक समान कार्यकलापों में प्रवृत्त उद्यमों पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि इससे एक संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान संबंधी प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें, राहतें और कटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के एक समान कार्यकलाप करने वाले उन उद्यमों पर लभने वाले कराधान तथा संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः किसी तीसरे संविदाकारी राज्य के एक निवासी अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं।

4. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है, जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं हैं, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपायों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह

मामला उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पांच वर्षों के अन्दर हर हालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण वह कराधान लगाया गया है जो इस अभिसमय के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को समझित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण को दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति से उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा, चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें, पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी ऐसे कराधान के अन्तर्करण के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनमें अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ सीधे-पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जहां समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान किया जाना उपयुक्त समझा जाता हो तो इस प्रकार का विचार-विमर्श एक आयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि होंगे।

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के करों से संबंधित घरेलू कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं, जहां तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से ऐसे करों की जालसाजी अथवा अपयंत्रण को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गयी सूचना मानी जाती है। तथापि, यदि उक्त सूचना को सूचना भेजने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है, तो उसे ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली, उनके संबंध में प्रवर्तन

अथवा अभियोजन की कार्यवाही अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में अंतर्ग्रस्त हों, जो इस अभिसमय के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही परिजनों के लिए करेंगे परन्तु वे उस सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्शों के माध्यम से, उन मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पद्धतियों और तकनीकों का विकास करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसमें, जहाँ-कहीं उपयुक्त हो, कर-परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाये :

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना या दस्तावेजों को देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है ;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों को देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद 27

राजनयिक और कौंसली अधिकारी

इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक एजेन्टों अथवा कौंसली अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 28

प्रवर्तन

1. इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथासंभव शीघ्र ब्राजिलिया में किया जाएगा।

2. यह अभिसमय, अनुसमर्थन-दस्तावेजों का आदान-प्रदान होने पर लागू होगा और इसके उपबंध पहली बार निम्नलिखित के लिए प्रभावी होंगे :

(क) ब्राजील में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है, उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गयी अथवा जमा की गयी राशि पर, स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में ;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारणीय वर्ष के लिए अभिसमय द्वारा समाविष्ट अन्य करों के संबंध में।

(ख) भारत में :

जिस कैलेंडर वर्ष में अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में प्राप्त होने वाली आय के संबंध में।

अनुच्छेद 29

पर्यवसान

संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य, अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् पड़ने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के जून मास के केवल 30वें दिन अथवा उसके पहले राजनयिक माध्यम से पर्यवसान का लिखित नोटिस दूसरे संविदाकारी राज्य को देकर इस अभिसमय को समाप्त कर सकेगा।

(क) ब्राजील में :

- (i) जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस दिया जाये उसके तत्काल परवर्ती कैलेंडर वर्ष में जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् अदा की गयी अथवा जमा की गयी राशि पर, स्रोत पर रोक लिए गए करों के संबंध में ;
- (ii) जिस कैलेंडर वर्ष में पर्यवसान का नोटिस दिया जाये उसके तत्काल परवर्ती कैलेंडर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्षों के लिए अन्य करों के संबंध में।

(ख) भारत में :

जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाये उसके तत्काल परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में प्राप्त होने वाली आय के संबंध में।

जिसके साथ में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में अप्रैल, 1988 के 26 वें दिन को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, जिसके सभी तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत के गणराज्य की ब्राजील के संघीय गणराज्य की
सरकार के लिए सरकार के लिए

पी. के. अपाचू ओक्तावियो हाइनो दा सिल्वा नेविस

प्रोटोकॉल

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपव्ययन को रोकने के लिए भारत के गणराज्य और ब्राजील के संघीय गणराज्य के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करते समय इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी निनिलिखित उपबन्धों पर सहमत हो गए हैं जो इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे।

1. अनुच्छेद 3, पैराग्राफ 1, मद (छ) के सन्दर्भ में यह समझा जाता है कि "कर" शब्द में वह राशि शामिल नहीं होगी, जो उन करों, जिन पर वह अभिसमय लागू होता है के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की भूल अथवा चूक के लिए देय राशि हो अथवा उन करों के सन्दर्भ में लगाए गए अर्थ-दण्ड की राशि हो।

2. अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 3 के सन्दर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3 के उपबन्ध किसी भी ऐसे व्यक्ति को अव्यवहार, प्रशासनिक वैधानिक, तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सहायता अथवा सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से की गयी अदायगियों पर भी लागू होंगे जो इस प्रकार की अदायगियाँ करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की गयी अदायगियों से भिन्न हों।

3. अनुच्छेद 20 के सन्दर्भ में

यह समझा जाता है कि "संग्रहालय अथवा अन्य सांस्कृतिक संस्थानों" शब्दों से अभिप्राय केवल ऐसे संगठनों से है, जिन्हें इस संबंध में सम्बन्धित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

4. अनुच्छेद 24, पैराग्राफ 2 के सन्दर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 के उपबन्ध अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबन्धों से परस्पर विरोधी नहीं हैं।

5. यह समझा जाता है कि दोनों संविदाकारी राज्यों से से कोई भी संविदाकारी राज्य अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीख से, किसी भी समय, लेकिन दस वर्ष से पहले नहीं,

अपने सक्षम, प्राधिकारी के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देकर इसके किसी भी उपबन्ध अथवा सभी उपबन्धों की समीक्षा करवा सकता है। सक्षम प्राधिकारी उसने पञ्चाद छः महीनों की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा के लिए उपयुक्त कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

जिसके साथ में, इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो-हस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में अप्रैल, 1988 के 26 वें दिन को हिन्दी, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, जिसके तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत के गणराज्य ब्राजील के संघीय गणराज्य के
के लिए लिए

पी. के. अपाचू ओक्तावियो हाइनो दा सिल्वा नेविस

[अधिबूचना संख्या 9020/(फा.सं. 501/4/84-एफ.टी.डी.)]

एन. सी. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

(INCOME-TAX)

G.S.R. No. 381(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the Instruments of Ratification exchanged at Brasilia on 11th March, 1992 as required by Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE
REPUBLIC OF BRAZIL

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Federative Republic of Brazil.

Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which the Convention shall apply are :

- (a) in the case of Brazil :
 - the federal income tax, excluding the supplementary income tax and the tax on activities of minor importance; (hereinafter referred to as "Brazilian tax");
- (b) in the case of India :
 - (i) the income tax including any surcharge thereon;
 - (ii) the surtax; (hereinafter referred to as "Indian tax").

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the above-mentioned taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "nationals" means :
 - I—all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
 - II—all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State;
- (b) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Brazil or India, as the context requires;
- (c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(g) the term "tax" means Brazilian tax or Indian tax, as the context requires;

(h) the term "competent authority" means :

I—in Brazil : the Minister of Finance, the Secretary of Federal Revenue or their authorized representative;

II—in India : the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purpose of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;
- (h) an installation, drilling rig or ship used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business

in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of the Contracting State concerned.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

4. The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of persons, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterer of the ships or aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is a company which is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a resident of India has a permanent establishment in Brazil, this permanent establishment may be subject to a tax withheld at source in accordance with Brazilian law. However, such a tax cannot exceed 15 per cent of the gross amount of the profits of that permanent establishment determined after the payment of the corporate tax related to such profits.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 :

- (a) interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State, a political subdivision thereof or any agency (including a financial institution) wholly owned by that Government, or political sub-division shall be exempt from tax in the first-mentioned State, unless sub-paragraph (b) applies ;
- (b) interest from securities, bonds or debentures issued by the Government of a Contracting State, a political sub-division thereof or any agency (including

a financial institution) wholly owned by that Government or political sub-division shall be taxable only in that State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

6. The tax rate limitation provided for in paragraph 2 shall not apply to interest arising in a Contracting State and paid to a permanent establishment of an enterprise of the other Contracting State which is situated in a third State.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, by a reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed :

- (a) 25 per cent of the gross amount of the royalties arising from the use or the right to use trade marks ;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, films or tapes for television or radio broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident

of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6, which is situated in the other Contracting State, may be taxed in the other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in the other State. However gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 and 2, may be taxed in both Contracting States.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State, unless the remuneration for such services or activities is paid by a resident of the other Contracting State or is borne by a permanent establishment situated therein. In such case, the income may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, technical, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if ;

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or of any council of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by an entertainer or an athlete if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of, or sponsored by the other Contracting State, including those of any political sub-division or local authority.

Article 18

PENSIONS AND SOCIAL SECURITY PAYMENTS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration, alimony and annuities paid to a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

2. However, such pensions and other similar remuneration, alimony and annuities may also be taxed in the other Contracting State if the payment is made by a resident of that other State or a permanent establishment situated therein.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

4. As used in this Article :

- (a) the term "pensions and other similar remuneration" means periodic payments made in consideration of past employment or by way of compensation for injuries in connection with past employment ;

(b) the term "annuities" means stated sums payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 19

GOVERNMENTAL PAYMENTS

1. Remuneration not including pensions, paid by a Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, to a political sub-division or local authority shall be taxable only in that State.

However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident if the service are rendered in that State and the recipient of the remuneration is a resident of that State who

(a) is a national of that State, or

(b) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, to a political sub-division or a local authority thereof may be taxed in that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions paid in respect of services rendered in connection with any business carried on by a Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof.

Article 20

TEACHERS AND RESEARCHERS

1. An individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who, at the invitation of the Government of the first-mentioned State or of a university, college, school, museum or other cultural institution of that first-mentioned State or under an official programme of cultural exchange, is present in that State for a period not exceeding two consecutive years solely for the purpose of teaching, giving lectures or carrying out research at such institution shall be exempt from tax in that State on his remuneration for such activity provided that the payment of such remuneration is derived by him from outside that State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 21

STUDENTS AND APPRENTICES

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1, a student or business, apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting.

3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than five consecutive years from the date of his first arrival in that State.

Article 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, arising in the other Contracting State and not dealt with in the foregoing Articles of this Convention, may be taxed in that other State.

Article 23

METHODS FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. Subject to the provisions of paragraphs 3 and 4, where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in that other State.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in that other State.

2. For the deduction, mentioned in paragraph 1, the tax paid in that other State shall always be deemed to have been paid at the rate of 25 per cent of the gross amount of interest referred to in paragraph 2 of Article 11 and of royalties referred to in paragraph 2b of Article 12, provided however, that the tax so deemed to have been paid shall not exceed the tax leviable on that income in the first-mentioned State.

3. Where a company which is a resident of a Contracting State derives dividends which, in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 10, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall exempt such dividends from tax.

4. Where a resident of India derives profits which, in accordance with the provisions of paragraph 5 of Article 10 may be taxed in Brazil, India shall exempt such profits from tax.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.

4. In this Article, the term "taxation" means taxes to which this Convention applies.

ARTICLE 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within five years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraph. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

PROTOCOL

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Brasilia as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force upon exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect for the first time :

(a) in Brazil :

I—in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the Convention enters into force;

II—in respect of other taxes covered by the Convention, for the taxable year beginning on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the Convention enters into force.

(b) in India :

in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April immediately following the calendar year in which the Convention enters into force.

Article 29

TERMINATION

Either Contracting State may terminate this Convention after a period of five years from the date on which the Convention enters into force by giving to the other Contracting State, through diplomatic channels, a written notice of termination, provided that any such notice shall be given only on or before the thirtieth day of June in any calendar year.

In such case the Convention shall cease to have effect :

(a) in Brazil :

I—in respect of taxes withheld at source, to amounts paid or credited on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given;

II—in respect of other taxes, for taxable years beginning on or after the first day of January of the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given.

(b) in India :

in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April immediately following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto have signed this Convention.

Done at New Delhi this 26th day of April 1988, in duplicate in Hindi Portuguese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India. For the Government of the Federative Republic of Brazil

Sd/-

P. K. APPACHOO

Sd/-

OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES

At the moment of the signature of the Convention between the Republic of India and the Federative Republic of Brazil for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income the undersigned, being duly authorised thereto, have agreed upon the following provisions which constitute an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 3, paragraph 1, item (g).—It is understood that the term "tax" shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. With reference to Article 12, paragraph 3.—It is understood that the provisions of paragraph 3 of Article 12 shall apply to payments of any kind to any person, other than payments to an employee of a person making such payments, in consideration for the rendering of assistance or services of a managerial, administrative, scientific, technical or consultancy nature.

3. With reference to Article 20.—It is understood that the terms "museum or other cultural institution" shall refer only to such organisations which have been approved in this regard by the competent authority of the Contracting State concerned.

4. With reference to Article 24, paragraph 2.—It is understood that the provisions of paragraph 5 of Article 10 are not in conflict with the provisions of paragraph 2 of Article 24.

5. It is understood that either Contracting State may, at any time not earlier than ten years from the date on which the Convention enters into force, seek to review any or all of its provisions, by notice in writing through competent authority thereof to the competent authority of the other Contracting State. The competent authorities shall, within a period of six months thereafter, initiate appropriate proceedings for such review.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Protocol.

Done at New Delhi this 26th day of April 1988, in duplicate in Hindi, Portuguese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India

Sd/-

P. K. APPACHOO

For the Government of the
Federative Republic of Brazil.

Sd/-

OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES

[Notification No. 9020/F. No. 501/4/84-FTD]

N. C. JAIN, Jt. Secy.

